The Cotton Corporation of India has already constructed two godowns at Kalamboli, New Mumbai, Maharashtra which are fairly modern with storage capacity upto 8000 bales, while an additional two godowns are currently under construction.

Introduction of Comprehensive Transport Policy

2048. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to introduce a comprehensive transport policy;

(b) whether new transport policy is going to be announced during the current year;

(c) if so, the salient features of that policy; and

(d) the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (d): The Standing Committee of Parliament on Transport and Tourism on the Demands for Grants of the Ministry of Surface Transport has *inter alia* recommended the formulation of an integrated approach to Surface Transport. Sinch this will involve other modes of transport like railways and civil aviation also in addition to Road Transport the Planning Commission was requested by Ministry of Surface Transport to take lead in the matter and it was proposed to set up a National Transport Coordination Committee for this purpose. However, to expedite the matter Ministry of Surface Transport approached the Planning Commission to persuade the Steering Committee on Inter-Modal Linkages and Programmes to undertake this exercise. The Planning Commission has maintained that the exercise by the Steering Committee has a limited scope for the 9th Five Year Plan whereas integrated Transport Policy will have a longer perspective going beyond 9th Five Year Plan. The Ministry of Surface Transport has already approached the external funding agencies like ADB and UNDP for necessary assistance in this regard. In these circumstances it would not be possible to draw up and announce any new Transport Policy during the current year.

Participatory Irrigation Management

2049. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government have given high priority to the Participatory Irrigation Management scheme in the irrigation management;

(b) if so, the steps Government have taken to expedite the activities in this respect;

(c) whether there is any special assistance provided to State Governments for the rehabilitation works to expedite scheme; and

(d) if so, the details thereof and the assistance provided to the State of Gujarat in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir. The Union Government have given priority to Participatory Irrigation Management Scheme in the irrigation management.

(b) The following steps have been taken to expedite farmers, participation in the management of irrigation:

— Giving management subsidy to farmers' associations under centrally sponsored Command Area Development Programme;

— Holding National Conferences and sponsoring State Level and Project Level Conferences on Participatory Irrigation Management with farmers' participation in the State and Project level Conferences to create awareness.

— Conducting training courses at national level for officers and at State level for officers and farmers;

— Providing States with guidelines and assisting them in preparation of Manuals for formation of associations and introducing amendments in Irrigation Acts;

— Advising State Governments to constitute High Level Working Groups to formulate policies and guidelines for constituting farmers' associations; and

— Setting up of "Working Group by Planning Commission on Participatory Irrigation Management for the IX Plan."

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

राज्यों में नदी जल का बंटवारा

2050. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राज्यीय जल के मामले में राज्यों के हिस्से निर्धारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा विभिन्न प्रमुख नदियों में अपने-अपने हिस्सों के लिए किये गये दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख नदियों से जल के बंटवारे के लिए किए गए दावों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**)

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 6 के अनुसार अधिकरण का निर्णय अंतिम एंव विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तथा इसे उनके द्वारा लागू किया जाएगा।

विवरण

वृहद अन्तर-राज्यीय नदियों के संबंध में दावा की गई हिस्सेदारी और आबंटित जल का विवरण नीचे दिया गया है:—

1. कृष्णा जल विवाद अधिकरण

यूनिट: टी.एम. सी.
(हजार मिलियन क्यूबिक फुट)

राज्य	दावे की मात्रा	आबंटित		
		75% निर्भरता योग्य प्रवाह	वापिसी प्रवाह	कुल
आन्ध्र प्रदेश	2008.1	800	11	811
कर्नाटक	1432.4	700	34	734
महाराष्ट्र	828.8	560	25	585
		2060	70	2130

2. गोदावरी जल विवाद अधिकरण

क. दावा की गई हिस्सेदारी

महाराष्ट्र: 1951 के समझौते को अमान्य घोषित किया जाये, राज्यों के हिस्से की मात्रा एक समान हो आदि।

कर्नाटक: 1951 के समझौते आदि पर ध्यान न देते हुए मंझारी वितरणी के उपलब्ध जल में समान हिस्सेदारी के अनुसार 75 प्रतिशत विश्वसनीयता।

मध्य प्रदेश: 1951 के समझौते को अमान्य घोषित किया जाए, अपने राज्य के भीतर अपने अंशदान की सीमा तक गोदावरी बेसिन में प्रवाहित होने वाले जल का उपयोग करने का अधिकार आदि।

उड़ीसा: इसके जलग्रहण से सम्पूर्ण जलप्रवाह का प्रयोग और नियंत्रण करना अथवा दूसरी ओर कुछ अन्य मांगों के साथ 478.270 टी एम सी का प्रयोग करना।

आन्ध्र प्रदेश: वर्ष 1951 के समझौते के अनुसार अन्य विभागों के साथ गोदावरी नदी की 2500 टी एम सी की विश्वसनीय प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1951 से पहले वचनबद्ध परियोजनाओं के लिए दैनिक आधार पर 1960 के बीच की वचनबद्ध परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक आधार पर वैकल्पिक रूप से पूर्ण तथा समय पर आपूर्ति।

ख. अधिकरण द्वारा आबंटन

गोदावरी जल विवाद अधिकरण ने 2495 टी एम सी का 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह राज्यवार आबंटित नहीं किया है लेकिन इसे अलग-अलग समझौतों द्वारा राज्यों के बीच कुछ शर्तों के साथ परियोजनाओं के कुछ स्थानों पर आबंटित किया है।

3. कावेरी जल विवाद अधिकरण

कावेरी जल विवाद अधिकरण में बेसिन राज्यों द्वारा दावा किए गए कावेरी जल का वास्तविक हिस्सा इस प्रकार है:

(i) कर्नाटक — 465 टी एम सी फुट

(ii) तमिलनाडु — वर्ष 1892 और 1924 के समझौतों के अनुसार प्रवाह सुनिश्चित किया जाना है।

(iii) केरल — 99.8 टी एम सी फुट

(iv) पांडिचेरी — 9.3 टी.एम सी फुट

अधिकरण ने 25 जून, 1991 को अन्तरिम पंचाट दिया जिसमें कर्नाटक को निदेश दिया गया कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए अनुसार जल वर्ष में मैत्तूर जलाशय में 205 टी एम सी जल सुनिश्चित किया जाए और तमिलनाडु